खाकी पुलिस इन्वेस्टीगेशन में जातिवाद के लिए जगह नहीं

विकास नारायण राय

क्या उत्तर प्रदेश किसी जातिवादी विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है? योगी शासन का शायद यही मानना है।

हाथरस को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। वहां के 14 सितंबर के दलित बलात्कार-हत्या मामले में पुलिस इन्वेस्टीगेशन की दशा-दिशा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक / राजनीतिक तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। व्यापक षड्यंत्र के नाम पर प्रदेश भर में दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं और तमाम गिरफ्तारियां भी। लेकिन, सरकारी पहल और सामान्य समझ के बीच जातिवादी आयामों की भूमिका के घुस जाने से कानून-व्यवस्था का पहलू इस कदर विषम हो गया है कि मुख्यमंत्री ने जिसे जातिगत तनाव बढ़ाने का षड्यंत्र करार दिया है, विरोधियों के लिए वह योगी शासन के जातिवादी तौर-तरीकों का ही विस्तार हुआ।

हाथरस के बलात्कार-हत्या इन्वेस्टीगेशन में कमियों पर अनेकों सवाल हैं। विरोधियों और विशेषज्ञों की ओर से ही नहीं स्वयं शासन की ओर से भी। इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा मामले का 1 अक्तूबर को संज्ञान लेने के बाद हाथरस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) समेत इन्वेस्टीगेशन से जुड़े 5 पुलिस अधिकारी निलंबित हुए, और ऐसे वीडियो सामने आये जिनके आधार पर जिलाधिकारी (डीएम) को पीड़ित पक्ष पर मीडिया से बात न करने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगता रहा। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को 12 अक्तूबर सुनवाई के लिए बुला रखा है, मुख्यत: जानने के लिए कि पीड़ित के शव का रात के अँधेरे में, निकट परिवार को जबरन दूर रख कर, दाह संस्कार करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है। आखिर प्रशासन क्या छिपाना चाहता है और किसके इशारे पर?

मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी निष्पक्षता के दावे के साथ सर्वोच्च न्यायालय जा पहुंची, यह प्रार्थना लेकर कि बलात्कार-हत्या इन्वेस्टीगेशन का जिम्मा सीबीआई को दे दिया जाए, जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में समय सीमा के भीतर कार्यभार संपन्न करे। जबकि पीड़ित पक्ष पहले ही केस को सीबीआई को दिए जाने के योगी के निर्देश को ठुकराकर सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर न्यायिक जांच की मांग कर चुका है। इस सुनवाई के दौरान, जो एक हफ्ते बाद जारी रहेगी, कई वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक एसआईटी जांच की मांग कर डाली। बहरहाल, क्या इस ताबड़तोड़ पहल से योगी सरकार की नीयत पर सवाल खत्म हो जाएंगे या शक चलता रहेगा?

दरअसल, मुख्य अपराध के तथ्यों और निष्कर्षों को लेकर शुरू से ही दो विपरीत नैरेटिव चल रहे हैं। पहली नजर से ही समझ में आने लगता है जैसे सरकार और पुलिस ने आरोपी ठाकुर पक्ष के निर्दोष होने का विवरण मान लिया हो। एफआईआर में बलात्कार का जिक्र न करना और अपराध के 8 दिन बाद पीड़ित का मेडिकल कराना अगर काफी नहीं थे तो किसी काल्पनिक शांति भंग की हवाई आशंका में गुपचुप दाह संस्कार करना तो किसी के भी गले नहीं उतरेगा। पुलिस का फॉरेंसिक जांच में सीमेन न मिलने को ही बलात्कार न होने का पर्याय मान लेना और भी हास्यास्पद है। सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी ही बार कहा है कि बलात्कार एक आपराधिक परिघटना है जो इन्वेस्टीगेशन से सिद्ध होगी, न कि महज मेडिकल या फॉरेंसिक जांच से। अन्यथा भी, 2013 में धारा 75 आईपीसी (बलात्कार की परिभाषा) में निर्भया संशोधन के बाद से सीमेन का मिलना नहीं, किसी भी अंग या वस्तु का बिना सहमति के प्रवेश ही निर्णायक होगा।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी हठधर्मिता रही कि उनकी ओर से हाथरस के पीड़ित दलित पक्ष को ही कदम-कदम पर सफाई देने के लिए कहा गया- यहाँ तक कि झूठ पकड़ने वाला लाई डिटेक्टर टेस्ट और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका नारको टेस्ट तक लेने को। जबकि हाथरस काण्ड में मिली जबरदस्त प्रशासनिक किरकिरी के समानांतर ही प्रचार में आये बलरामपुर दलित बलात्कार-हत्या मामले में योगी के एडीजी, लॉ एंड आर्डर ने अपराध की गुरुता का हवाला देकर, दोनों मुस्लिम अपराधियों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाने की मंशा जाहिर कर डाली। हाथरस में चूक क्यों?

गंभीर अपराध के इन्वेस्टीगेशन पर जातिवाद की छाया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है

किसी गंभीर अपराध के इन्वेस्टीगेशन पर जातिवाद की छाया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कही जायेगी। यह राजनीतिक प्रवृत्ति पुलिस की जांच को तो पटरी से उतारेगी ही, समाज को भी कानूनी अनिश्चितता का शिकार बनाएगी। यहाँ फरीदाबाद, हरियाणा के सुनपेड़ गाँव काण्ड पर एक नजर डालना ठीक रहेगा, जिसमें 39 महीने की जांच-पड़ताल के बाद सीबीआई ने 2019 में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दी थी।

एफआईआर के मुताबिक 20 अक्टूबर 2015 की देर रात कुछ लोगों ने दलित समुदाय के जितेंद्र के घर में खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इसमें उसकी 28 वर्षीय पत्नी रेखा गंभीर रूप से झुलस गई थी। जबकि उसके ढाई साल के बेटे वैभव और 11 महीने की बेटी दिव्या की मौत हो गई थी। 31 वर्षीय जितेंद्र भी झुलस गया था। मामले में, पुरानी रंजिश के चलते, गाँव के बलवंत इत्यादि ठाकुर समुदाय के 10 लोगों को नामजद किया गया था।

पीड़ित पक्ष की ओर से जिला पुलिस की एसआईटी से इन्वेस्टीगेशन सीबीआई को देने की मांग हुयी थी। सीबीआई ने पाया कि आग बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही लगी है, जिस वजह से आरोपितों पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। मामले में जातिवादी तूल ने सामाजिक तनाव को बेतरह बढ़ाया और इन्वेस्टीगेशन को बेवजह भटकाया। जबकि हरियाणा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की 30 अक्टूबर 2015 को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक भी आग लगने की शुरुआत कमरे के भीतर से हुई थी और इसका स्रोत भी घर के भीतर ही था। जातिवाद, राजनीतिक हिंदुत्व की आत्मा सरीखा है। उसका ध्वंस महज संवैधानिक दायित्व नहीं, हिन्दू समाज का ऐतिहासिक कार्यभार भी है। ध्यान रहे कि सदियों तक राजनीतिक सत्ता से वंचित रहकर भी भारतीय भूभाग के समाज में जातिवाद फलता-फूलता रहा है।

हाथरस प्रकरण के सामाजिक और प्रशासनिक आयाम अनिवार्य रूप से रेखांकित करते हैं कि जातिवाद का अस्तित्व तभी मिटेगा जब पीढ़ियों से भुगत रहे तबके इसके राजनीतिक-सांस्कृतिक एजेंडे के ध्वंस की दिशा में पलटवार की निर्णायक पहल कर सकें। तभी भारतीय समाज को इस दुरात्मा से मुक्ति मिलेगी। समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय का यह रोडमैप बिना सामाजिक उथल-पुथल के तय नहीं किया जा सकता।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

राष्ट्रीय कोरोना काल में मोदी के लिए आलीशान विमान

यूसुफ किरमानी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष विमान को टक्कर देने वाले हवाई जहाज में उड़ेंगे। देश में जब नौकरी मांगते करोड़ों बेरोजगार युवा, खेती को बचाने के लिए लाखों किसान और अपने जंगल को बचाने के लिए सैकड़ों आदिवासी सड़कों पर हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री के विशेष विमान पर इस देश के खजाने से 8458 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। यह विमान भारत में उतर चुका है।

अमेरिकी राष्ट्रपति को छोड़कर अभी तक मोदी के दोस्त और इस्राइल के विवादास्पद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही सबसे महंगे विमान में उड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका में बनाया जा रहा विमान इस्राइली प्रधानमंत्री के विमान के मुकाबले चार गुणा सुरक्षित किले वाला और चार गुणा लग्जरी वाला है।

भारत सरकार ने एयर इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़े वाले दो बोइंग 777-300 विमानों को कस्टमाइज (यानी बदलाव करके फिर से बनाना) करके बनाने का निर्देश दिया था। इसे अमेरिका में तैयार किया गया है और इसे स्पेशल एक्स्ट्रा सेक्शन फ्लाइट (एसईएसएफ) या वीवीआईपी नाम दिया गया है। इस विमान में कभी कभी रष्ट्रपति भी उड़ सकेंगे। दो विमान की इस फ्लीट का दूसरा विमान इस साल के अंत तक आ सकता है।

हाल ही में इस कस्टमाइज विमान की खूबियां कुछ मीडिया रपटों में सामने आई थीं। इसके मुताबिक यह विमान अंदर से अभेद्य किले जैसा होगा। इसका अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसके अपने सेल्फ प्रोटक्शन स्यूइट्स (एसपीएस) है। दुश्मन के रडार सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को ये एसपीएस सिस्टम जाम करने में सक्षम है। इसके अलावा इस पूरे एसपीएस में कम्युनिकेशन सिस्टम अत्याधुनिक है ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसके बारे में अभी सुना तक नहीं गया है। इसके आडियो और वीडियो सिस्टम को कोई हैक नहीं कर सकेगा। ये सुविधाएं और तकनीक अभी तक सिर्फ अमेरिका के एयर फोर्स 1 विमान में है, जिसमें सिर्फ अमेरिकी रष्ट्रपति उड़ते हैं। इसीलिए इसे अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तरह अलग से एयर इंडिया 1 नाम दिया गया है। ऐसे एयरक्राफ्ट जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए होते हैं, उसमें 1 लगाने का चलन अमेरिका ने शुरू किया था।

भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए लेकिन आपकी प्राथमिकताएं क्या हों, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

हालांकि ये विमान एयर इंडिया की देखरेख में कस्टमाइज किए गये हैं लेकिन भारत में आने के बाद इनका कमांड और कंट्रोल एयरफोर्स के पास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस विमान में बिना ईंधन भराए इसे 17 घंटे तक लगातार उड़ाया जा सकेगा। भारतीय प्रधानमंत्री के पास अभी जो विशेष विमान है उसे बिना ईंधन भराए दस घंटे से ज्यादा नहीं उड़ाया जा सकता।

भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए लेकिन आपकी प्राथमिकताएं क्या हों, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देश के खजाने से 8458 करोड़ रुपये ऐसे समय खर्च किए जा रहे हैं, जब देश कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। इतने बजट में कई अच्छे अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए खोले जा सकते थे। हाल ही में देश के करोड़ो बेरोजगार युवकों ने प्रदर्शन कर भाजपा सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।

केंद्र सरकार तीन कृषि कानून लेकर आई लेकिन देश के दो बड़े कृषि प्रधान राज्यों पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इन कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है। खुद भाजपा और उसके सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के कई विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी। हरियाणा के रादौर में पूर्व भाजपा विधायक ने किसानों के मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी और अभय चौटाला की पार्टी इनैलो में शामिल हो गए।

पंजाब में भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अलग होकर गठबंधन ही तोड़ दिया। जाहिर है कि स्थितियां भाजपा के खिलाफ होती जा रही हैं और ऐसे में सरकारी खजाने से पैसा सिर्फ ऐशोआराम और सुरक्षा के नाम पर लुटाया जाएगा तो सवाल उठेंगे ही।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)